अनमोल विचार

हर मनुष्य को ये याद रखना चाहिए, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपना सम्मान नहीं कर सकते।

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

इस सप्ताह का विचार

जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है! उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती हैं!

-चाणक्य

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 27 February TO 4 March 2020 • VOLUME-25 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

जिलाधीश के दोहरे मापदंड आम जनता पर भारी

जालंधर ब्रीज द्वारा पुराने अंकों में दर्शाई गई हाईवे में त्रुटियों की कुछ तस्वीरें।

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

पिछले कई दिनों से जालंधर के जिलाधीश यातायात नियमों ,रोड सेफ्टी और शहर में हो रही अवैध इमारतों और इलीगल रोड एक्सेस को लेकर नैशनल हाईवे के अधिकारी नगर-निगम के टाऊन प्लानरस,और पुडा के टाऊन प्लानरस को दिशा-निर्देश देते हुए पाए जाते हैं कि शहर के विकास को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और मास्टर प्लैन के हिसाब से सड़कों के आस-पास बिल्डिंगों का निर्माण हो हाईवे पर कहीं भी बिल्डिंग मालिकों द्वारा गलत तरीकों से एक्सेस लिया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इसकी दो हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा जिलाधीश को यह सब चीज़ों में शहर की गंभीर समस्या पी.ए.पी फ्लाईओवर, रामामंडी फ्लाईओवर के बाद दकोहा फाटक पठानकोट चौक से लेकर भोगपुर तक हाइवे को छोटा बनाना जिसमें टू-व्हीलर के लिए कोई व्यवस्था का ना होना फ्लाईओवर जोकि फोरलेनींग ही रहने दिए जिनको नैशनल हाईवे के अधिकारियों की डिजाइन टीम द्वारा सिक्स लेन ना करना और उनकी नालायकी की वजह से परिवहन मंत्री जो कि प्रमुख राजमार्गों कि स्पीड लिमीट को 90 कि.मी प्रति घंटा से 100 कि.मी प्रति घंटा बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है परन्तु जालंधर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा पी.ए.पी चौक से सरब मल्टीप्लैकस फ्लाईओवर तक इसको 50 कि.मी प्रति घंटा करके इन दोनों को खोखला कर दिया है एक विधायक जो वैसे ही जालंधर की सियासत में सबसे कमज़ोर चल रहा है उसको धरना देकर कानून अपने हाथों में लेना पड़ रहा है।

परन्तु जिलाधीश होते हुए आज तक इनके विरुद्ध कार्रवाई करने को क्यों नहीं बिजीलैंस विभाग को लिखा गया ना ही जिला पुलिस को लिखा गया और ना ही केन्द्र की सरकार को लिखा गया परन्तु केन्द्र के अधिकारी हाईवे पर सारी त्रुटीयों के लिए जिला प्रशासन को लिखित में जिम्मेवार ठहराते हैं। जिसके लिखित में कई सबूत दिये जा सकते हैं परन्तु यह तो वहीं हिसाब हुआ कमजोर को डराते हो तगड़े के आगे झुक जाते हो।

सोनिया गांधी ने दिल्ली हिंसा को साजिश

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 20 पर पहुंच गई है। इस हिंसा को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने आज कहा कि दिल्ली हिंसा पर सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक हुई। उन्होंने इस हिंसा और दुखद घटनाओं के पीछे साजिश करार दिया। सोनिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी साजिश देखी गई, भाजपा नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर भय का माहौल बनाया। दिल्ली में मौजूदा हालात के लिए केन्द्र सरकार, गृह मंत्री और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सोनिया ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में हिंसा के लिए जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री भी शांति बनाए रखने में नाकाम रहे, सीडब्ल्यूसी का मानना है कि स्थिति गंभीर है, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया जाना चाहिए, मोहल्लों में शांति समितियों का गठन किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रभावित इलाकों में जाना चाहिए और लोगों के साथ लगातार संवाद करना चाहिए। सीडब्ल्यूसी लोगों से घृणा की राजनीति को अस्वीकार करने और दरारें भरने के लिए बेहतर कदम उठाने की अपील करती है। सोनिया ने सवाल किया कि रविवार से गृहमंत्री शाह और केजरीवाल कहां थे, क्या कर रहे थे?

BALAKOT AIR STRIKE ANNIVERSARY

जब हमने दुश्मन देश को दिया संदेश- घुस कर मारेंगे

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

जब भी बालाकोट एयरस्ट्राइक का जिक्र होता है, हर भारतीय को अपने सैनिकों के कामों पर छाती गर्व चौड़ी हो जाती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को बुधवार एक साल पूरा हो गया। 29 फरवरी 2019 को भारत ने पौ फटने से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े शिविर को तबाह कर दिया जिसमें कई आतंकवादी और उनके प्रशिक्षक मारे गए। पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद इन आतंकवादियों को उनकी सुरक्षा के लिए इस शिविर में भेजा था। दो मिनट से भी कम समय में इसे अंजाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना का यह हमला अत्यंत त्वरित और सटीक था। भारत के इस पलटवार को पुलवामा हमले का बदला माना जाता है। बारह दिन पहले ही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं, केवल आतंकी ठिकाने पर किया गया और इसे 'हमलों को रोकने' के उद्देश्य से 'ऐहतियात' के तौर पर अंजाम दिया गया था। यह ठिकाना जंगल में एक पहाड़ी पर स्थित था और पांच सितारा रिजॉर्ट शैली में बना था। इसके चलते यह 'आसान निशाना' बन गया तथा आतंकवादियों को नींद में ही मौत के आगोश में सुला दिया गया था। यह शिविर बालाकोट में स्थित था। संदर्भ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित शहर का था जो नियंत्रण रेखा से करीब 80 किलोमीटर दूर और ऐबटाबाद के नजदीक स्थित है जहां अमेरिकी बलों ने 2011 में अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। वायुसेना के विमानों ने आतंकी शिविरों को बर्बाद करने के लिये एक हजार किलोग्राम वजन के कई लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। अभियान की शुरूआत तड़के 3.45 पर हुई जो 4.05 बजे तक चला जबकि वास्तविक हमला करीब दो मिनट ही चला। युद्धक विमानों ने अभियान के लिए कई वायुसैनिक अड्डों से उड़ान भरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर जगकर पूरे अभियान पर नजर रखे हुए थे और तभी आराम करने गए जब सभी लड़ाकू विमान और पायलट सुरक्षित लौट आए थे।

बालाकोट एयरस्ट्राइक के एक साल पूरे होने परपूर्व वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा कि एक साल बीत चुका है और हम संतुष्टि के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, बालाकोट के संचालन के बाद बहुत सारी चीजें लागू की गई हैं। मूल रूप से, यह हमारे कार्यों को संचालित करने के तरीके में एक बदलाव है। दूसरे पक्ष ने कभी नहीं माना कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी प्रशिक्षण शिविर को बर्बाद कर देंगे। हमने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। धनोआ ने कहा कि बालाकोट हवाई हमले के बाद, पूरे भारतीय चुनावों में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ क्योंकि वे डर गए थे कि हम फिर से उसी तरीके से या और भी विनाशकारी तरीके से जवाब देंगे। जो संदेश हम देना चाहते थे, वह था, घुस कर मारेंगे चाहे आप कोई भी हों। अन्यथा, हम उन पर अपने क्षेत्र से भी हमला कर सकते थे।

दिल्ली हिंसा: मोदी ने की स्थिति की समीक्षा, शांति एवं भाईचारा बनाये रखने की अपील की

नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली में हिंसा की घटनाओं के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोगों से शांति एवं भाईचारा बनाये रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की है। मोदी ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जल्दी शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ''दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान हालात की गहन समीक्षा की। पुलिस एवं अन्य एजेंसियां सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिये काम कर रही हैं।'' मोदी ने कहा, ''हमारे संस्कार के मूल में शांति, सौहार्द है। मैं दिल्ली के बहनों, भाइयों से शांति और भाईचारा बनाये रखने की अपील करता हूं।''

गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले समूहों के बीच संघर्ष ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया था। उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों तथा वाहनों में आग लगा दी और एक-दूसरे पर पथराव किया। इन घटनाओं में बुधवार तक कम से कम 20 लोगों की जान चली गई और करीब 200 लोग घायल हो गए।

बिजली विभाग की टीली कार्यप्रणाली से वार्ड नं. 66 के लोग आने वाले दिनों में सड़कों पर उतर सकते है

■ जालंधर/विजय कुमार

पंजाब में कांग्रेस की सरकार रोजाना दोषपूर्ण की सरकार अकाली-भाजपा सरकार पर प्राईवेट कंपनियों के साथ किए गए बिजली के करारों पर ठीकरा फोड़ती है कि इन करारों के कारण पंजाब में मंहगी बिजली हमें देनी पड़ रही है परंतु अपने तीन साल के कार्याकाल में बिजली विभाग के भ्रष्ट अफसर महंगी बिजली देकर भी पूरी बिजली नहीं दे रही है इसके लिए क्या वो जिम्मेवारी लेती है। जालंधर ब्रिज लोगों की समस्याओं को अपने समाचारपत्र में प्रकाशित कर प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करता आ रहा है।

इसकी कड़ी में ही एक मुद्दा वार्ड नं. 66 में पिछले दो साल से लंबित पड़ा है प्रकाश आइसक्रीम के पास लगे ट्रांसफोर्मर और डाक खाने के पास लगे ट्रांसफोर्मर जोकि कम कैपिसीटी का है यह समस्या कई बार उक्त अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है परन्तु हैरानीजनक बात तो यह सामने आई है कि विभाग द्वारा दिए गए जवाब पत्र नं. सी.एम. ऑफिस/ ई/2019/ 00802 नं. 93130/19-20 लिख कर यह आश्वासन दिया कि इस काम के लिए कुल खर्ची 3,04557/- रूपये आएगा जिसको पिछले कई सालों से लंबित पड़े एस्टीमेट को पास करवा लिया गया हैं अब यह कब लगेगा यह विभाग को खुद नहीं पता क्योंकि यह सिर्फ कागजों में ही पास हुआ है इसकी टैंडरिंग प्रक्रिया कब होगी और कब किसी ठेकेदार को काम दिया जाएगा या विभाग अपने भ्रष्ट अफसरों से ही यह काम करवाएगा क्योंकि यहां का पार्षद तो आज़ाद जीता है और विधायक मौजूदा सरकार से है और इसका जवाब लोग 2022 में दोनों नेताओं को दे ही देंगे परन्तु यह जाँच का विषय है कि इस काम को अभी तक क्यों नहीं करवाया गया क्योंकि जल्द ही गर्मियां आने वाली है और लोग गर्मी में तड़पेंगे विभाग के भ्रष्ट इंजीनीयर्स अपने घरों में एसी कमरों में सोएंगे और लोगों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर इस समस्या का हल आने वाले 15 दिनों में ना निकाला गया तो इन अफसरों के घरों का घेराव करके इनके परिवारों को भी सोने नहीं दिया जाएगा।

कम कपैसटी वाला खराब पड़ा ट्रांसफार्मर

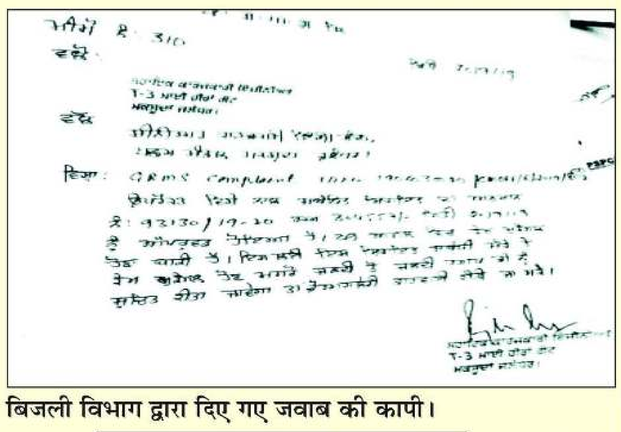

बिजली विभाग द्वारा दिए गए जवाब की कापी।

दिल्ली हिंसा: चांदबाग में मिला खुफिया विभाग कर्मी का शव, हत्या कर नाले में फेंक दिया गया था

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा की वजह से लगभग 20 लोगों की जाने जा चुके हैं। इस बीच इस हिंसा में एक खुफिया विभाग के कर्मी की भी मौत हो गई है। खुफिया विभाग के इस कर्मी का नाम अंकित शर्मा है। इसका शव आज चांद बाग़ में बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार पथराव में अधिकारी की हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अंकित शर्मा चांद बाग इलाके में रहते थे और शायद पथराव में उनकी जान गई। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। अंकित चांद बाग़ का ही रहने वाला था। वह ड्यूटी से घर लौट रहा था तभी उसकी पथराव में हत्या कर दी गई थी। परिवार वाले जानकारी जुटाने में लगे हुए थे। परिवार वालों ने हत्या के पीछे एक स्थानीय नेता का हाथ बताया है जो कि उनके घर के पास ही रहता है।

अंकित चांद बाग का ही रहने वाला था। वह ड्यूटी से घर लौट रहा था तभी उसकी पथराव में हत्या कर दी गई थी। परिवार वाले जानकारी जुटाने में लगे हुए थे। परिवार वालों ने हत्या के पीछे एक स्थानीय नेता का हाथ बताया है जो कि उनके घर के पास ही रहता है।

परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था तभी उसे चांद बाग पुलिया पर कुछ लोगों ने घेर लिया और उसके पीट-पीटकर हत्या कर दी। अंकित के पिता रविंद्र शर्मा खुफिया विभाग में हेड कांस्टेबल है।

दखल

पैसे का संकट और बढ़ता प्रदूषण

प्रदूषण का संकट पूरी दुनिया के लिए जितना भयावह है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए यह समस्या गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी है कि प्रदूषण के कारण भारत में होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतों वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। लेकिन यह काम अकेले सरकार या किसी संस्था के भरोसे मुमकिन नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक प्रदूषण की समस्या का समाधान होने की उम्मीद नहीं है।

देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि इसे मापने का पैमाना छोटा पड़ रहा है। खासकर वायु प्रदूषण के मामले में तो पूरी दुनिया में भारत की स्थिति काफी खराब है। उत्तर भारत के कई इलाके गैस चैंबर में तब्दील होते जा रहे हैं। इसीलिए इस बार के बजट से काफी उम्मीद लगाई गई थीं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट में कुछ बड़ा प्रावधान किया जाएगा। यह उम्मीद और ज्यादा इसलिए भी थी, क्योंकि सरकार ने पिछले साल ही राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य यह था कि 2017 को आधार वर्ष मान कर 2024 तक पीएम-10 और पीएम-2.5 को बीस से तीस फीसद तक कम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत उन 122 शहरों पर काम किया जाना था, जहां प्रदूषण की तीव्रता तय मानकों से ज्यादा रहती है। कार्यक्रम चालू हुए एक साल गुजर चुका है। कार्रवाई योजना को लागू करने की कई कोशिशें हुईं भी, लेकिन अब तक असर दिखाई नहीं दिया। कार्रवाई योजना के अलावा भी विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए थे। लेकिन ये सारे उपाय काफी खर्चीले थे। प्रदूषण का दायरा है भी इतना बड़ा कि छोटे-मोटे उपायों से फर्क नहीं पड़ने वाला। संभवतः इसीलिए इस बार के बजट में प्रदूषण और पर्यावरण के मद में रकम का प्रावधान पिछले साल की तुलना में दस गुना ज्यादा रखा गया है। हालांकि समस्या के सामने यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। फिर भी इस काम की शुरुआत के लिए काफी है, बशर्ते शुरुआत भी ढंग से हो।

पिछले साल प्रदूषण से निपटने के लिए बजट में सिर्फ 460 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस बार यह रकम बढ़ा कर 4400 करोड़ रुपए कर दी गई है। गौर से देखें तो प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले साल के बजट में प्रावधान एक तरह से नगण्य ही था। इसीलिए इस बार साढ़े चार हजार करोड़ की रकम कई गुनी ज्यादा दिख रही है, लेकिन इस रकम से बड़ी मुश्किल से देश के कुछ शहरों में ही प्रदूषण निरोधी उपाय लागू किए जा सकेंगे। इसीलिए पहले से कह दिया गया है कि इस रकम का लाभ वे ही शहर उठा पाएंगे, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है। यानी प्रदूषण कम करने की शुरुआत चुनिंदा शहरों तक सीमित रहेगी। देश में दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की संख्या 84 है। विशेषज्ञों का अनुमान यह है कि एक शहर में प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के लिए औसतन साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस लिहाज से सालाना बजट की 4400 करोड़ रुपए की रकम दो शहरों के लिए भी काफी नहीं है। हालांकि एनसीएसी के तहत 122 शहर चिन्हित किए गए थे। यानी इस बार के बजट में एलान किए गए दस लाख आबादी से छोटे शहर नजर से बाहर हो गए हैं। फिर भी प्रदूषण के मोर्चे पर खर्च के लिए धन की कमी के कारण कुछ न होने से तो इतना होना भी बहुत माना जाएगा।

आम बजट में पर्यावरण को अचानक थोड़ा बहुत महत्व मिलने पर अचरज होना स्वाभाविक है, क्योंकि देश भारी आर्थिक संकट में है। उसकी पहली चिंता देश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने को लेकर है और सारी दुनिया जानती है कि औद्योगिक गतिविधियां पर्यावरण से समझौता किए बगैर संभव नहीं हैं। इस सिलसिले में अब तक जितनी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वे इसीलिए नाकाम हुईं क्योंकि ज्यादातर देशों ने अपने आर्थिक विकास की चिंता सबसे पहले की। यहां तक कि खुद अमेरिका तक पेरिस समझौते से अलग हो चुका है और बेहिचक एलान कर चुका है कि आर्थिक वृद्धि से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा। जाहिर है, इस घटना का असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है। आमतौर पर यह समझा जाने लगा है कि आर्थिक हित सबसे पहले हैं और पर्यावरण या दुनिया के नागरिकों की सेहत की चिंता बाद की बात है। इसीलिए अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्यादातर देश प्रदूषण की समस्या से आंखें चुराते रहे हैं। लगभग सभी देश कार्बन उत्सर्जन अपने तय लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं कर पाए। जलवायु परिवर्तन की चिंता को लेकर अतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वाद-विवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इस समय प्रदूषण का संकट पूरी दुनिया के लिए जितना भयावह है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए यह समस्या गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी है कि प्रदूषण के कारण भारत में होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है।

दुनिया में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतों वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। ग्लोबल अलांयस ऑन हेल्थ एंड पॉल्युशन ने यह रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं भागीदार हैं। प्रदूषण और स्वास्थ्य पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स इवेल्यूएशन के आंकड़े इस्तेमाल करते हुए बताया है कि हर साल सभी प्रकार के प्रदूषण से पूरी दुनिया में 83 लाख लोग मर रहे हैं। किसी भी बीमारी या प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों की तुलना में यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। आज दुनिया में एचआइवी, टीबी और मलेरिया से होने वाली मौतों की तुलना में प्रदूषण से होने वाली मौतें तीन गुना ज्यादा हैं। युद्ध और दूसरी तरह की हिंसा में होने वाली मौतों की तुलना में यह आंकड़ा करीब 15 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में प्रदूषण के विभिन्न रूपों का भी ब्योरा है। इससे यह पता चलता है कि सबसे भयावह हालत वायु प्रदूषण की है। इससे दुनिया में हर साल करीब 50 लाख लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 70 लाख है। ऐसे में जरूरत फौरन युद्धस्तर पर काम करने की है। भारत इस समय चौतरफा प्रदूषण की आपात स्थिति में है। वायु प्रदूषण चरम पर है। जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन भी व्यापक रूप से प्रदूषित हो रहे है। खासतौर पर देश में जल संसाधन जिस तरह कम पड़ता जा रहा है, उसमें सीमित जल का प्रदूषित होते जाना बड़े संकट का संकेत है। उधर, उत्पादकता बढ़ाने की होड़ में कीटनाशकों और अंधाधुंध रासायनिक खाद का इस्तेमाल अब पूरी खाद्य श्रृंखला को जहरीला बना रहा है।

कुछ समय पहले ही भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्वेक्षण में देश भर से उठाए गए दूध के नमूनों में एफलोटॉक्सिन नाम का खतरनाक पदार्थ हद से ज्यादा पाया गया था। ऐसे में प्रदूषण से मौतों के मामले में भारत को शीर्ष पर रखे जाने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 40 फीसद ऊर्जा उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से करने का लक्ष्य बनाया था। यही नहीं, इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 2005 की तुलना में 2030 तक 35 फीसद तक कम करेंगे। वन क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण जैसे कई उपायों को लागू करने पर भी भारत विभिन्न मंचों पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, लेकिन इन कामों को करने में हमेशा ही पैसे की कमी आड़े आती रही। इस बार के बजट में वायु प्रदूषण के मद में तय 4400 करोड़ की रकम स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन जैसे उपायों के लिए भले ही नाकाफी लगे, लेकिन इससे प्रदूषण पर निगरानी का काम जरूर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह काम अकेले सरकार या किसी संस्था के भरोसे मुमकिन नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक प्रदूषण की समस्या का समाधान होने की उम्मीद नहीं है।

विचार

हिंसा से किसी का भला नहीं

ट्रंप के दौरे के बीच सीएए का विरोध सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मगर ऐसा विरोध जो देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, उससे तो परहेज किया ही जाना चाहिए। क्या हमें इस तरह से गैर जिम्मेदार होने का उदाहरण पेश करना चाहिए।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में भड़की हिंसा के तार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से जुड़ते दिख रहे हैं। सरकार कह रही है कि ट्रंप के सामने इस मुद्दे को बड़ा बनाने के मकसद से ही हिंसा भड़काई जा रही है। ट्रंप के दौरे से पहले रविवार को पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं। सोमवार को हिंसा ऐसी भड़की कि उसमें 5 जिंदगियां खाक हो गईं। मंगलवार को भी मामला शांत नहीं हुआ। सुबह से पथराव और वाहनों में आग लगाने का सिलसिला चलता रहा। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के बीच सीएए का विरोध सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मगर ऐसा विरोध जो देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, उससे परहेज तो किया ही जाना चाहिए। एक देश का राष्ट्रपति जब भारत, वह भी दिल्ली में हो, तो क्या हमें इस तरह से गैर जिम्मेदार होने का उदाहरण पेश करना चाहिए, यह सवाल हर उस शख्स को खुद से पूछना चाहिए, जो हिंसा में शामिल रहा है। यह सब करके हम क्या साबित करना चाहते हैं। ट्रंप भारत में एक खास मकसद लेकर आए हैं।

अमेरिका में कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। वहां ट्रंप को जीत हासिल करने के लिए भारतीयों का समर्थन चाहिए। फिर अपने देश में बने उत्पादों को बेचना भी उनका काम है। सो, वे कुछ मौकों पर सेल्समैन की तरह भी रहेंगे। अब भला इसमें सीएए का मुद्दा कहां से आ गया। ट्रंप क्यों सीएए पर बात करेंगे और करेंगे भी तो भारत उनकी क्यों सुनेगा। हिंदुस्तान की सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, न कि अमेरिका के...यह बात हिंसा कर रहे लोगों को समझनी होगी। हम पढ़े-लिखे जाहिलों जैसा व्यवहार कर भारत की साख पूरी दुनिया में गिरा रहे हैं और दुनिया को जगहंसाई करने का मौका दे रहे हैं। सरकार कई बार कह चुकी है कि कानून नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एनआरसी अभी संसद में पास तो क्या पेश भी नहीं किया गया है। फिर किस बात का डर। शाहीनबाग में 70-75 दिनों से सड़क जाम कर बैठी या बैठाई गईं महिलाओं को यह सच क्यों नहीं बताया जा रहा।

वे कह रही हैं कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो कोई उन्हें बताए कि उनके बच्चों का भविष्य जितना भारत में सुरक्षित है, उतना कहीं और नहीं। चीन में मुस्लिमों पर रोजा तक रखने पर पाबंदी है। फ्रांस समेत कितने देशों में बुर्का प्रतिबंधित कर दिया गया है। खुद पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं पर ढेरों पाबंदियां हैं। मगर आजादी की मांग भारत में हो रही है। आखिर आजादी चाहिए किस चीज से। अगर हम आजादी चाहते हैं तो खुद की गुलाम मानसिकता से मुक्ति की मांगें। कोई भी हमें बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है और हम उसकी बातों में आकर अपना घर-कारोबार चौपट कर बैठते हैं और फिर पछताते रहते हैं।

नेटबंदी के समांतर सवाल

डिजिटल इंडिया के युग में जिस तरह नेटबंदी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे भारत की छवि पूरी दुनिया में प्रभावित हो रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा ग्रहण लगता है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाती है, वहां दूरसंचार कंपनियों को तो भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ता है, साथ ही तमाम तरह की आर्थिक, व्यावसायिक व सामाजिक गतिविधियां भी करीब-करीब ठप-सी हो जाती हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान इंटरनेट बंदी के मामले में भारत दुनियाभर में पहले पायदान पर रहा है। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार अलग-अलग परिस्थितियों में अलग कानूनों का सहारा लेती है, जिनमें आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 शामिल हैं। पहले सूचना के प्रचार-प्रसार सहित इंटरनेट सेवा बंद करने का अधिकार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और धारा-144 के तहत सरकार और प्रशासन को दिया गया था, पर टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 अस्तित्व में आने के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अब अधिकांशतः इसी प्रावधान के तहत लिया जाने लगा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जो इंटरनेट को मानवाधिकार की श्रेणी में शामिल करता है और सरकारों द्वारा इंटरनेट पर रोक लगाने को सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन बताता है, लेकिन यह प्रस्ताव किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है।

पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय नागरिकता कानून के खिलाफ देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कई जगह इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में अभी तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगी है। हालांकि 145 दिनों की पाबंदी के बाद बीते 27 दिसंबर को लद्दाख के करगिल क्षेत्र में इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। इसके अलावा घाटी के ज्यादातर अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवा फिर से चालू हो गई है। नेट सेवा बंद किए जाने को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से सदैव यही तर्क दिया जाता रहा है कि किसी तरह के विवाद या बवाल की स्थिति में हालात बेकाबू होने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफवाहों, गलत संदेशों, खबरों, तथ्यों और फर्जी तस्वीरों के प्रचार-प्रसार के जरिए विरोध की चिंगारी दूसरे राज्यों तक न भड़कने देने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ता है। इसमें दो राय नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों द्वारा झूठे संदेश व फर्जी वीडियो वायरल कर माहौल को खराब करने के प्रयास किए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के बाद भी ऐसे इलाकों में हिंसक घटनाएं और उपद्रव होते हैं। ऐसे में नेट पर पांबदी का कदम कई सवाल भी खड़े करता है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाए जाने से देश को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इंटरनेट बंदी लोगों की जिंदगी को थाम देती है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी को चलाए रखने से जुड़े अनेक काम अब नेट सेवाओं के जरिए ही होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि एक तरफ जहां सरकार हर सुविधा के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दे रही है और कई सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, वहीं हिंसक आंदोलनों से निपटने के लिए क्या नेट बंदी ही बड़ा कदम रह गया है, क्या इसका और कोई विकल्प नहीं है? शोधकर्ताओं का दावा है कि इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद भी हिंसा और प्रदर्शनों को रोकने में कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है। लोगों का काम-धंधा जरूर चौपट हो जाता है और व्यक्तिगत नुकसान के साथ सरकार को भी बड़ी आर्थिक चपत लगती है। एक अनुमान के अनुसार देश में आज 48 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमें जीवन के हर कदम पर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों की जिंदगी काफी हद तक कंप्यूटर-इंटरनेट की दुनिया से जुड़ गई है।

किसी को अपना आधार कार्ड बनवाना या ठीक कराना हो या अन्य किसी सरकारी सेवा का लाभ उठाना हो अथवा ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या खाने का ऑर्डर करना हो या फिर ऑनलाइन कैब, टैक्सी, रेल व हवाई टिकट बुक करना हो, बिना इंटरनेट के इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करना असंभव हो जाता है। इंटरनेट शटडाउन के चलते एक ओर जहां ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेटबंदी की स्थिति में कोई अपनी फीस, बिजली व पानी के बिल, बैंक की ईएमआई आदि समय से नहीं भर पाता, तो बहुत से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने और इंटरनेट का उपयोग कर उनकी तैयारी करने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। डिजिटल इंडिया के युग में जिस तरह नेटबंदी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे भारत की छवि पूरी दुनिया में प्रभावित हो रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा ग्रहण लगता है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाती है, वहां दूरसंचार कंपनियों को तो भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ता है, साथ ही तमाम तरह की आर्थिक, व्यावसायिक व सामाजिक गतिविधियां भी करीब-करीब ठप-सी हो जाती हैं और अरबों का आर्थिक नुकसान होता है।

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2012 से लेकर 2017 के दौरान हुई नेटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 22 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2011 से 2017 तक भारत में करीब सोलह हजार घंटे इंटरनेट बंद रहा, इससे देश को करीब 213 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि पांच महीनों की नेटबंदी के कारण करीब सौ अरब रुपए का भारी-भरकम नुकसान हो चुका है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) का कहना है कि देश में नेटबंदी के कारण हर घंटे करीब ढाई करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसलिए सरकार को इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से पहले विचार करना चाहिए। डिजिटल इंडिया के इस दौर में नेटबंदी का मतलब 'डिजिटल डार्कनेस' की ओर बढ़ना है। पिछले साल भारत में सौ से ज्यादा बार इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगी। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध एक विश्व रिकॉर्ड है। हालांकि उससे पहले भी जुलाई 2016 में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद राज्य में आठ जुलाई से 19 नवंबर 2016 तक चार महीने से भी अधिक समय इंटरनेट बंद रखा गया था। साल 2017 में गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के चलते करीब सौ दिनों तक दार्जिलिंग में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था।

नेटबंदी से लोगों का जीवन और आर्थिक गतिविधियां ठप न हों, इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार को ऐसे विकल्प तलाशने की जरूरत है जिनसे नेटबंदी की नौबत ही न आए। मसलन, प्रभावित इलाकों में पूरी तरह इंटरनेट बंद करने के बजाय फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल साइटों पर भी अस्थायी पाबंदी लगाई जा सकती है। ऐसे ही कुछ और उपाय भी तलाशे जा सकते हैं, जिनसे पूर्ण इंटरनेट शटडाउन जैसे हालात से बचा जा सके।

ट्विटर

हिंसा से कोई समाधान नहीं होता है। सभी लोग शांति बनाए रखें। दिल्ली में पुलिस की संख्या कम है। केंद्र सरकार अब पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आदेश दे।

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

यह बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए जनता को बरगलाने में लगे हैं जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर हैं।

मनोज तिवारी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली

सत्यार्थ

ईमानदारी का इनाम

सिंगापुर में एक अंग्रेज डॉक्टर सिसिल ब्राउन अकेले ही रहते थे। अपने यहां पले जानवरों को वह बच्चों की तरह प्यार करते थे। 14 साल का एक लड़का मिग उनके कपड़े धोता व प्रेस करता था। वह भी अकेला रहता था। तभी अंग्रेजों व जापानियों में युद्ध छिड़ गया और मिग घायल हो गया। वह डॉ. ब्राउन के पास पहुंचा। ब्राउन ने उसकी मरहम-पट्टी की और दवा देते हुए कहा- तुम मेरे कुछ कपड़े लेते जाओ, उन्हें धो कर प्रेस व करके दे जाना। दो दिन बाद सिंगापुर पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। अन्य कैदियों के साथ मिग को भी जेल में डाला गया। जापानी सेना ने ब्राउन को भी जेल भेज दिया। तीन साल बाद सिंगापुर पर फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जापानियों द्वारा बंदी बनाए गए सभी कैदी छूट गए। ब्राउन और मिग भी जेल से छूटकर घर लौट आए। मिग ने सबसे पहले ब्राउन के कपड़े धोए और उन पर प्रेस की। फिर कपड़े ले कर वह ब्राउन के घर पहुंचा। पहले मिग ने उन्हें सलाम किया, फिर कपड़ों का बंडल थमा दिया। ब्राउन ने उससे पूछा- इसमें क्या है? उसने कहा- सर, इस बार मुझे बहुत देर हो गई। जापानियों ने मुझको जेल में डाल दिया था। याद है न आपको, तीन साल पहले आपने यह कपड़े मुझे धोने के लिए दिए थे। ये रहे आपके कपड़े। मैं परसों ही जेल से छूटा हूं। उसकी ईमानदारी देखकर ब्राउन की आंखें नम हो गईं। वे बोले- मेरे बच्चे, मैं भी जेल से कल ही छूटकर आया हूं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं अपना सारा दर्द भूल गया। मिग, अब तुम अनाथ नहीं हो। तुम मेरे साथ रहोगे एवं कपड़े नहीं धोओगे। कल से तुम स्कूल जाना। अपने देश को भी आज डॉ. ब्राउन जैसे लोगों की जरूरत है, जो अनाथ और गरीब बच्चों का सहारा बनें।

मयूरभंज में हजारों परिंदे करते हैं इस ट्रैफिक पुलिस अफसर का इंतजार, जानते हो क्यों?

ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा कस्बे में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को ज्यादातर लोग बर्डमैन के नाम से जानते हैं। उन्हें यह पहचान एक अनूठी आदत की वजह से मिली है। उनकी यह आदत पिछले 10 साल से नहीं बदली है। वह रोजाना शहर के हजारों कबूतरों और दूसरे पक्षियों को दाना खिलाते हैं।

ड्यूटी करते वक्त कंधों पर बैठ जाते हैं कबूतर

सूरज कुमार राज (52) बारीपदा टाउन पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक पुलिस अफसर के रूप में तैनात हैं। वह कस्बे के अलग-अलग इलाकों में पक्षियों को दाना चुगाते हैं। अपनी इस आदत के बारे में राज बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की जॉब की तरह मैंने इन पक्षियों को खिलाने की ड्यूटी भी अपने हाथों में ली है। मैं उन्हें प्यार करता हूं, क्योंकि वे मुझे प्यार करते हैं। कई बार जब मैं ड्यूटी पर रहता हूं तो वे मेरे पास आकर कंधों पर बैठ जाते हैं।

दाना निकालने से पहले ही पहुंच जाते हैं परिंदे

राज कहते हैं कि भीड़ के बीच भी ये पक्षी उन्हें पहचान लेते हैं। हर सुबह हजारों कबूतर उनका इंतजार करते रहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए दाना निकालने से पहले ही कबूतर इस बर्डमैन ट्रैफिक पुलिस अफसर के पास पहुंच जाते हैं। राज का कहना है कि जब मैं इन पक्षियों को खिलाता हूं तो मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं गाय जैसे दूसरे पशुओं को भी खिलाता हूं। जैसे ही वे मुझे बाइक से आते देखते हैं, वे मेरी तरफ चले आते हैं।

पुलिस विभाग को अपने बर्डमैन पर गर्व

एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एएसपी) अविमन्यु नायक का कहना है कि स्थानीय लोग उन्हें बर्डमैन के नाम से पुकारते हैं और हमें उनकी सेवा पर गर्व है। एएसपी नायक कहते हैं कि वह पिछले कई सालों से इन पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। हमें उन पर बहुत गर्व है। वह अपने काम के प्रति काफी संजीदा हैं।

सीख

दुनिया आपको कैसे देखती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आप खुद को कैसे देखते हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

जीवन में जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करते हैं, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है।

आपकी मेहनत ही तय करती है सफलता

अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अगर हम हार मान ले रहे हैं, तो हम सचमुच हार गए, लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार-बार गिर कर खड़े होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है, तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता है। यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। यही बात इस कहानी में भी बताई गई है।

एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जो जीवन में हार मान चुका था। वह जिंदगी में जो कुछ भी करता था, उसको अपनी हार पहले ही नजर आ जाती थी। स्कूल में अध्यापक और अन्य विद्यार्थी भी उसकी मजाक उड़ाते थे। वह अंधेरे कमरे में अक्सर रोता रहता था।

एक दिन उसकी सिसकियां सुनकर एक अंधा आदमी उसके पास आया और पूछा कि 'तुम क्यों रो रहे हो'? राहुल ने उस आदमी को सारी बात बताई। यह सुनकर वह आदमी जोर से हंसा और बोला कि तुम्हें पता है, 'जब मैं पैदा हुआ और लोगों ने देखा कि इस बच्चे की तो आंखें ही नहीं है, तो उन्होंने मेरे माता-पिता को मुझे मार देने की सलाह दी', लेकिन मेरे माता-पिता ने उन लोगों की सलाह नहीं मानी।

उन्होंने मुझे एक विशेष स्कूल में भेजा और मुझे पढ़ाया-लिखाया। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो कॉलेज प्रशासन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। फिर मैंने विदेशी विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा और एमआईटी की स्कॉलरशिप पर स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ली, लेकिन जब मैं वापस आया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि नेत्रहीन होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा था या मेरे पास कोई अनोखा आईडिया था। मैंने कंपनी इसलिए शुरू की, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी कंपनी के जरिए मेरे जैसे 5000 लोगों को नौकरी दे पाया हूं।

आदमी की बात को सुनकर राहुल ने पूछा कि आप की कहानी से मेरा क्या वास्ता? वह आदमी बोला, जैसे आज लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वैसे ही जिंदगी भर लोगों ने मेरी भी निंदा की, मेरा भी मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा। जब दुनिया मुझे नीची नजरों से देखती थी और यह कहती थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तब मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे मैंने इतना सब कुछ किया वैसे ही तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए हिम्मत मत हारो। दुनिया क्या कहती है, इस बात की परवाह मत करो।

अनाथ बच्चों को थाने में पढ़ा-लिखा रहा है एक सिपाही

फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ या खानाबदोश की जिंदगी जीने वाले मजदूर, भिखारी या घुमंतू समुदाय के बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। इनके छोटे-छोटे बच्चों को राजस्थान पुलिस के एक सिपाही धर्मवीर जाखड़ कलम पकड़ा कर शिक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मवीर ने अपनी संस्था 'मुस्कान' के जरिए दुबई की जेल में कैद चार राजस्थानी मजदूरों को छुड़ाने का भी काम किया है। चुरू जिले की राजगढ़ तहसील स्थित खारिया गांव के निवासी धर्मवीर ने सड़क किनारे रहने वाले बच्चों को आज से चार साल पहले पढ़ाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने 2016 में चुरू पुलिस लाइंस के पास एक जगह चुनी और वहां महिला थाने से सटी दीवार के किनारे 3 से 4 बच्चों को जमा कर उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। इसका नाम जाखड़ ने 'आपणी पाठशाला' रखा।

भीख देने की बजाय दी शिक्षा

वह बताते हैं कि मैं थाने में जब ड्यूटी कर रहा होता था तो वहां कुछ बच्चे हमेशा भीख मांगने आते थे। उन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा विचार आता था कि इन बच्चों को भीख देने की बजाए इनका भविष्य संवारना चाहिए। महज 3-4 बच्चों से शुरू हुई 'आपणी पाठशाला' में चार साल बाद आज 450 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्हें जाखड़ ने सरकार के सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ रखा है। ज्यादातर बच्चे राजस्थान, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के हैं। 'आपणी पाठशाला' में पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। स्कूल चलाने के लिए जगह न होना मुख्य समस्या है।

आसान नहीं है काम

अस्थायी बसेरा होने से बच्चे कभी दो-दो महीने गायब रहते हैं। इनका पता लगाकर इन्हें नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलाते है। इनके पैरेंट्स को समझाते हैं। इस अभियान की तारीफ राहुल गांधी, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत जैसे कई नेता कर चुके हैं। यहां हमेशा 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं। पांचवीं पास होने के बाद बच्चों का दूसरे स्कूल में दाखिला होता है। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को लाने के लिए संस्था की ओर से दो बसें चलाई गई हैं। यहां उन्हें मुफ्त में दो वक्त का खाना दिया जाता है।

दुबई में फंसे मजदूरों को भी छुड़ाया

धर्मवीर ने बताया कि अपनी संस्था 'मुस्कान' के जरिए उन्होंने दुबई की जेल में कैद चार राजस्थानी मजदूरों को छुड़ाया। वहां इन्हें बड़ी गाड़ियों का लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बड़ी गाड़ियां चलाने और उसकी चपेट में आकर मारे गए या जख्मी हुए लोगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पैसा न होने से ये लोग वहां 8-8 साल तक जेल में बंद रहे हैं। ऐसे 4 मजदूरों को सवा करोड़ रुपए खर्च कर छुड़ाया गया। ये रकम जन सहयोग से जमा की गई। इन मजदूरों के भी बच्चे आपणी पाठशाला में पढ़ते हैं।

ऐक्टिंग छोड़ किसान बन गया यह पॉपुलर स्टार

अब जी रहा ऐसी लाइफ

बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया में कई ऐसे स्टार्स रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में टॉप पर पहुंच कर या तो कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लिया या फिर हमेशा के लिए शोबिज इंडस्ट्री ही छोड़ दी। इन्हीं स्टार्स में से एक हैं एक्टर अनस राशिद, जो दीया और बाती हम और धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान से घर-घर में मशहूर हो गए।

करियर के टॉप पर पहुंच कर छोड़ी ऐक्टिंग

अनस राशिद का करियर जिस वक्त टॉप पर था, उसी वक्त उन्होंने ऐक्टिंग के साथ-साथ टीवी छोड़ने का भी फैसला कर लिया। ऐक्टिंग छोड़ने के बाद अनस राशिद ने खुद से कई साल छोटी हीना इकबाल से शादी कर ली, जो कि चंडीगढ़ में एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं।

अब अपने गांव में खेती कर रहा है अनस

आज अनस टीवी इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर अपने गांव यानी मालेरकोटला में खेती कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले दिए एक इंटरव्यू में अनस ने बताया था कि उन्होंने ऐक्टिंग से कम से कम 5 साल का ब्रेक लिया और अब वह पेशेवर किसान बन गए हैं। अनस ने आगे कहा था कि उनकी फसल अच्छी हो रही है और खेतों में ट्रैक्टर चलाकर उन्हें बहुत मजा आता है। उन्हें अपना यह काम काफी अच्छा लग रहा है और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है।

इन टीवी शोज से मिला स्टारडम

अनस राशिद ने एकता कपूर के पॉप्युलर टीवी शो कहीं तो होगा से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई और शोज में काम किया, लेकिन धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में टाइटल किरदार निभाकर वह पॉप्युलर हो गए थे। इसके बाद दीया और बाती में निभाए सूरज के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अनस न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं, बल्कि सिंगर भी हैं। इसके अलावा उन्हें उर्दू, अरबी और पारसी भाषा भी आती है।

अब तो कमबैक का कोई सवाल ही नहीं उठता

पिछले साल यानी 2019 में ही वह एक प्यारी सी बेटी के पिता भी बने हैं। अब देखना यह है कि अनस राशिद कब टीवी की दुनिया में वापसी करते हैं। वैसे कुछ वक्त पहले अनस ने कहा था कि बेटी के जन्म के बाद वह टीवी पर वापसी करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं।

राजस्थान के मयंक प्रताप ने रचा इतिहास

21 साल की उम्र में बन गए जज

राजस्थान के 21 वर्षीय मयंक प्रताप सिंह ने इतिहास रचा है। वह 21 साल की उम्र में जज बनने जा रहे हैं। मयंक ने बताया कि उन्हें आरजेएस परीक्षा की तैयारी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

आरजेएस परीक्षा में अपनी सफलता पर मयंक ने कहा कि जाहिर है बहुत खुशी हो रही है। मैंने उम्मीद की थी कि सेलेक्शन हो जाएगा पर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे और परिवार के लिए ये बहुत खुशी की बात है। घर में जब से रिजल्ट आया है खुशी का माहौल है। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके फाइनल इयर में था। उसके बाद मैंने तैयारी करनी शुरू की, जिससे मुझे ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ा। मैंने 11-12 घंटे मन लगाकर पढ़ाई की। लक्ष्य ये था कि परीक्षा शुरू होने से पहले मैं अपना सिलेबस खत्म कर सकूं और एग्जाम में अच्छा कर पाऊं।

क्योंकि फैसले के लिए उन्हें ऑब्जेक्टिवली सारे तथ्यों को देखना पड़ता है, उसके बाद फैसला देना होता है। मुझे लगता है कि ये गुण एक जज में होना बहुत जरूरी है।

तथ्य देखकर ही निर्णय देते हैं जज

आज समाज में कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित कर सकते हैं। बाहुबल और धनबल पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सभी प्रभावों से दूर रहें। जजमेंट देते समय ध्यान रखें कि वो सिर्फ जज हैं, वो अपने कोर्टरूम तक सीमित हैं। उसमें जो तथ्य उसके सामने आएंगे, उनको देखकर उसे निर्णय देना होगा न कि दूसरों की बातें सुनकर।

न्यूनतम आयु सीमा घटाना रहा काफी मददगार

21 वर्षीय मयंक ने यह भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न्यूनतम आयुसीमा को 23 से घटाकर 21 करना उनके लिए काफी मददगार साबित हुआ। पहली बार जब रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था, तब मैं परीक्षा देने योग्य नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने उम्र कम कर दी और मैं योग्य हो गया। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मैंने यह रैंक हासिल की।

अपनी सोच ही बनी मेरे लिए प्रेरणा

मयंक ने कहा कि उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 5 साल का बीएएलएलबी किया है। अपनी प्रेरणा के बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं 12वीं कक्षा में था, तब मुझे लगता था कि ज्यूडिशरी का समाज में कितना महत्वपूर्ण रोल है। न्यायालयों में पेंडिंग मामले बहुत ज्यादा हैं। मैं अपना योगदान देना चाहता था, जिससे लोगों को न्याय दे सकूं। शायद मेरे लिए वही प्रेरणा बनी, जिसकी वजह से ये किया।

ईमानदारी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण

यह पूछे जाने पर कि उनके हिसाब से एक अच्छा जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मयंक ने कहा कि सबसे पहले तो ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी से ही न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बना रहता है। मुझे लगता है कि संवेदनशीलता सामाजिक मुद्दों की तरफ बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं या बच्चों से संबंधित फैसले देने के मामले में मेरा मानना है कि जज के लिए भेदभावरहित होना बहुत जरूरी है,

अपनी सेवाएं देने के लिए मेरे पास लंबा समय

ये पूछे जाने पर कि 21 साल की उम्र में जज बनने से वो करियर के बारे में क्या सोचते हैं, मयंक ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजस्थान ज्यूडिशरी के लिए बेहतर साबित होऊंगा। कम उम्र में चयनित होने का यही फायदा होगा कि मेरे पास सेवाएं देने के लिए लंबा समय होगा। मुझे लगता है कि मुझे लोगों की सेवा करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा और मैं ज्यादा योगदान दे पाऊंगा। अपने शौक के बारे में वो बताते हैं कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उपन्यास वगैरह मैं बहुत पढ़ता हूं। इसके अलावा सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उसके साथ अटैच होता हूं, जो भी महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूं।

हिमस्खलन में दबे, कर्ज में भी फंसे...फिर भी न टूटे और आखिर कर लिया माउंट एवरेस्ट फतह

करीब 5 साल पहले नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में मौत को मात देने वाले पर्वतारोही बृजमोहन शर्मा (ब्रीज शर्मा नाम से मशहूर) के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अल्ट्रा मैराथन रनर भी हैं। 46 वर्ष के बृज इंडियन नेवी में कार्यरत हैं और पहले भारतीय हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करने के अलावा दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन रेस में से एक बैडवॉटर 135 और ब्राजील 135 रेस पूरा की है। अकल्पनीय सी दिखने वाली ये तीनों कामयाबियां हासिल करना चट्टान की तरह मजबूत इरादे रखने वाले इंसान के बस की ही बात है।

अब यह अगला मिशन

बृज मजबूत इरादों वाले इंसान हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं, उसे पूरा करके दम लेते हैं। 46 वर्षीय बृज का अगला मिशन है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होने वाली डिलिरियस वेस्ट रेस। यह 350.7 किमी की है और इसे फिनिश करने की समय सीमा 104 घंटे है। पिछले साल भी बृज ने इसमें हिस्सा लिया था और इसे 95 घंटे और 39 मिनट में पूरा किया था। इस बार उनका इरादा इस रेस को 80 घंटे से कम में पूरी करने का है।

...और यूं किया माउंट एवरेस्ट फतह

2015 में बृज ने माउंट एवरेस्ट फतह करने की कोशिश की, किंतु भूकंप आ जाने से नाकाम रहे। वह भूकंप के कारण हुए हिमस्खलन में दब गए, लेकिन जीवित बच गए। हालांकि जब वह घर लौटे, तो उन पर भारी भरकम कर्ज का बोझ हो गया था। स्पॉन्सर्स से कोई फंड नहीं मिलने से बृज की परेशानियां और बढ़ गईं। इस आर्थिक संकट से उबरने में उन्हें काफी वक्त लगा। शर्मा ने 2016 में अल्ट्रा मैराथन में शानदार वापसी की और अमेरिका में बेहद गर्म मौसम में होने वाली बैडवॉटर 135 अल्ट्र मैराथन (217 किमी) रेस को फिनिश करने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्होंने यह रेस 40 घंटे और 47 मिनट में पूरी की और वह यह रेस पूरी करने वाले सबसे तेज भारतीय बने। यही नहीं, 2017 में दूसरे प्रयास में वह माउंट एवरेस्ट पर भी जा पहुंचे।

शारीरिक क्षमताओं को दी चुनौती

पिल्लै ने बृज को बिना बताए वर्ष 2012 में हुई वसई विरार मेयर्स मैराथन के लिए उनका नाम रजिस्टर करवा दिया और रेस की एक रात पूर्व उन्हें जानकारी दी। बृज कहते हैं कि इस मैराथन से पहले मैंने जिंदगी में किसी रेस में हिस्सा नहीं लिया था। खैर, मैं मेयर्स मैराथन में दौड़ा और 5 घंटे और 38 मिनट में रेस पूरी की। रेस फिनिश करने में लंबा वक्त लगा और यहां तक कि आयोजकों ने मुझे फिनिशर मेडल तक नहीं दिया। मुझे यह अपना नहीं, बल्कि पिल्लै सर का अपमान लगा, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया था।

पर्वतारोहण से रनिंग की तरफ ऐसे आया झुकाव

बृज का जन्म वर्ष 1974 में राजस्थान के जयपुर में हुआ। 15 वर्ष की उम्र में मुंबई आने के कुछ वर्षों बाद वह इंडियन नेवी का हिस्सा बने। वह इंडियन नेवी के एडवेंचर सेल के भी कई सालों तक इंचार्ज रहे। इस दौरान उन्होंने हिमालय की वादियों और पश्चिमी घाट में कई कैंप लगाने के अलावा 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों पर एक दर्जन से ज्यादा बार चढ़ाई करने के मिशन की अगुवाई की। पर्वतारोहण से रनिंग की तरफ झुकाव कैसे हुआ, इस बारे में बृज ने एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाया। नेवी में नौकरी के दौरान वह नेवी में ही कार्यरत सुरेश पिल्लै के संपर्क में आए, जिन्होंने बृज को मैराथन दौड़ने के लिए प्रेरित किया।

पिछली रेस में रास्ता भटके, फिर भी नहीं हारी हिम्मत

लिरियस वेस्ट रेस भी कम कठिन रेस नहीं है। इस दौरान रनर को पहाड़ी रास्तों के साथ जंगलों से होकर गुजरना होता है। यहां तक कि रात में भी। कभी-कभार ऐसे इलाकों से पाला पड़ता है, जहां इंसान तो छोड़ो पशु-पक्षियों तक का नामो-निशान नहीं होता। ये जरूर है कि हर 20 किमी पर एक कैंप होता है, जिसमें पानी और अन्य जरूरी सामान और चिकित्सकीय मदद उपलब्ध रहती है। डिलिरियस वेस्ट रेस के अपने पिछले अनुभव के बारे में बृज ने कहा कि मैं कई बार तय रास्ते से भटक गया। एक दफा तो मुझे तय रास्ते पर आने में 4 घंटे तक लग गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो रेस और कम समय में फिनिश कर पाता।

रनिंग से मुझे खुशी और संतुष्टि दोनों मिलती हैं: बृजमोहन

बृज ने हिम्मत नहीं हारी और अगले साल जनवरी में मुंबई मैराथन 4 घंटे और 31 मिनट में फिनिश करने के बाद अक्टूबर में अपनी पहली अल्ट्रा मैराथन (80 किमी भट्टी लेक्स अल्ट्रा) और दिसंबर में नीलगिरी की वादियों में 100 किमी की अल्ट्रा मैराथन दौड़ी। बृज को तब अहसास हो गया कि अल्ट्ररनिंग ही वह तरीका है, जिससे वह अपनी शारीरिक क्षमताओं को चुनौती दे सकते हैं। बृजमोहन शर्मा कहते हैं कि रनिंग से मुझे खुशी और संतुष्टि दोनों मिलती हैं। यह एक ऐसा खेल है, जिसमें कम से कम संसाधनों की जरूरत पड़ती है। कोई भी इंसान रनिंग करना शुरू कर सकता है। इंसान को जब भी वक्त मिले, उसे दौड़ना चाहिए। जीवन में कुछ बनने के लिए समय प्रबंधन बेहद जरूरी है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

स्मार्ट फोन पहले ही चीन से आर्डर किये जा चुके हैं, कोरोनावायरस के कारण हो रही है देरी-कैप्टन

■ चंडीगढ़/न्यूज नेटवर्क

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को कहा कि जब चीन पंजाब को स्मार्ट फोन भेजने के योग्य हो जायेगा तभी उनकी सरकार द्वारा किये वायदे के अनुसार स्मार्ट फोनों के पहले सैट का वितरण किया जायेगा। विधानसभा के दौरान राज्यपाल के भाषण के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि फोन पहले ही चीन से आर्डर किये जा चुके हैं, परन्तु बदकिस्मती से कोरोनावायरस के कारण फोन भेजने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कुछ सदस्यों

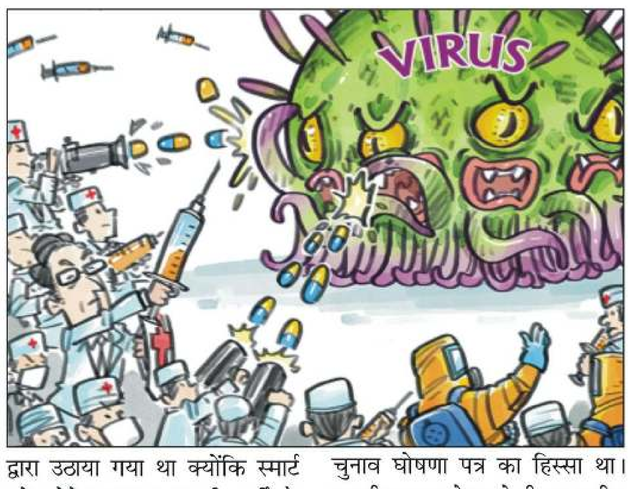

द्वारा उठाया गया था क्योंकि स्मार्ट फोन देने का वादा उनकी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। उनकी सरकार ने पहले ही इस स्कीम को नोटीफाई कर दिया था और चीन में स्वास्थ्य संकट के कारण फ़ोन खरीदने में देरी हुई और इस वायरस के कारण चीन में बाज़ार बंद हो गए जिसके नतीजे के तौर पर फोन की खेप प्राप्त नहीं हुई।

उन्होंने सदस्यों को भरोसा दिया कि फोनों की यह खेप प्राप्त होते ही फोन मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में कांग्रेस प्रधान ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले सभी राज्यों में अपने वादों को पूरा करने के लिए कमेटियां गठित की हैं और उनकी सरकार द्वारा स्मार्ट फोन देने का वादा निश्चित रूप में जल्द ही पूरा किया जायेगा।

स्पोर्ट्स

कीवी टीम ने विराट एंड गैंग के खिलाफ तैयार की अपनी रणनीति

■ क्राइस्टचर्च/न्यूज नेटवर्क

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने तेज और उछाल वाली गेंदों पर भारत के संघर्ष को देखते हुए बुधवार को कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को तेज गेंदबाजों के लिये अनुकूल हेगली ओवल में दूसरे टेस्ट मैच में 'चिन म्यूजिक' का सामना करना होगा।

वैगनर अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण वेलिंगटन टेस्ट मैच में नहीं खेल पाये थे जिसमें भारतीय बल्लेबाजों को राउंड द विकेट से की गयी शार्ट पिच गेंदों के सामने जूझना पड़ा था। वैगनर ने कहा कि उनकी टीम शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भी यही रणनीति अपनाएगी। वैगनर ने कहा, ''निश्चित तौर पर उनके लिये यहां खेलना मुश्किल होगा जहां थोड़ा अधिक उछाल और तेजी है। भारत में खेलने से यह भिन्न है जहां बहुत अधिक उछाल और तेजी नहीं होती है।''

कीवी कोच गैरी स्टीड की तरह वैगनर का भी मानना है कि भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे लेकिन उन्हें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम अपनी तरफ से किसी तरह की ढिलायी नहीं बरतेगी और मेहमान टीम की परेशानियां बढ़ाने में सफल रहेगी। उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि हम उन पर शिकंजा कसने में सफल रहेंगे और उसकी तरह से गेंदबाजी करेंगे जैसे

हमने वेलिंगटन में की थी। अगर हम दबाव बनाये रख पाते हैं तो इससे हम खुद के लिये काम आसान करेंगे।''

श्रृंखला छोटी है और इसलिए भारतीयों को परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिला। वैगनर ने कहा, ''कई बार जब आप विदेशी दौरों पर होते हैं तो परिस्थितियों से तालमेल बिठाने में एक या दो मैच लग जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और दमदार वापसी करेंगे।''

16 साल की शेफाली वर्मा ने मचाया टी-20 विश्व कप में धमाल, स्मृति मंधाना ने की तारीफ

■ मेलबर्न/न्यूज नेटवर्क

भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शीर्ष क्रम में अहम भूमिका निभाने वाली सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को खुशी है कि किशोरी शेफाली वर्मा महिला टी20 विश्व कप में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच रही है और उनका मानना है कि इससे टीम संतुलित बन गयी है।

पिछले दो-तीन वर्षों में भारतीय टीम का अहम अंग रही 23 वर्षीय मंधाना ने कहा कि शेफाली ने दिखा दिया कि वह उनकी तरह खेलने में सक्षम है। मंधाना ने कहा, ''पिछले दो तीन वर्षों में मैंने ढेर सारे रन बनाये विशेषकर पावरप्ले में लेकिन अब शेफाली भी उसी तरह से रन बना रही है जैसे मैं बनाती थी। इससे टीम अधिक संतुलित बन गयी है। वह जिस तरह से बल्लेबाजी करती है वैसे में उसके साथ बल्लेबाजी करना आसान है।''

सोलह वर्षीय शेफाली ने विश्व कप में अब तक दो मैचों में 68 रन बनाये हैं जिसमें पांच छक्के और सात चौके शामिल है। उनका स्ट्राइक रेट 212 है। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 39 रन बनाने के लिये मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। मंधाना बुखार के कारण इस मैच में नहीं खेल पायी थी।

मंधाना ने कहा, ''मैं पावरप्ले में अहम भूमिका निभाती रही हूं लेकिन अब शेफाली भी इन ओवरों में तेजी से रन बना रही है। उसने बड़ा प्रभाव छोड़ा है और टीम अधिक संतुलित बन गयी है।''न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को होने वाले मैच के बारे में मंधाना ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि

हम कुल स्कोर के बारे में सोचकर मैच में उतरेंगे लेकिन हम उस तरह से खेलना जारी रखेंगे जो कि हमारे बल्लेबाजों के अनुकूल है।''

न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज ली ताहुहु ने कहा कि वह शेफाली को गेंदबाजी करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, ''निजी तौर पर मुझे वर्मा का सामना करने के बारे में सोचना पसंद है। इससे मैं अधिक उत्साहित हो जाती हूं और मैं वास्तव में उसका सामना करने के लिये तैयार हूं।मैं पिछले साल भारत में टी20 चैलेंज में उसके साथ खेली थी और जानती हूं कि वह पीछे हटने वालों में नहीं है।''

सोनिया कर रही हैं हिंसा का राजनीतिकरण, शाह के इस्तीफे की मांग हास्यापद:भाजपा

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में हुई हिंसा की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने बुधवार को कहा कि अब हिंसा समाप्त हो रही है और सच्चाई सामने लाने के लिये जांच भी शुरु हो गई है, ऐसे में सभी दलों की प्राथमिकता शांति स्थायी होनी चाहिए। साथ ही पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग को हास्यापद करार दिया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली की हिंसा पर जो बयान दिया है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।'' उन्होंने कहा कि दिल्ली में हिंसा समाप्त हो रही है और सच्चाई सामने लाने के लिये जांच भी शुरु हो गई है।''हमारा विश्वास है कि पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आएगी।'' जावड़ेकर ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि वे पहले दिन से ही शांति बहाली के प्रयास में लगे हुए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। सोनिया ने आरोप लगाया ''यह (हिंसा) एक सोचा-समझा षड्यंत्र है। भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर नफरत और भय का माहौल पैदा किया।'' भाजपा के वरिष्ठ नेता जावड़ेकर ने किसी का नाम लिये बिना कहा कि जांच में यह बात भी सामने आ जायेगी कि किसने पथराव की तैयारी की, किसने वाहनों में आग लगायी और कौन पिछले दो माह से लोगों को उकसा रहा था। उन्होंने कहा ''कांग्रेस पूछ रही है कि अमित शाह कहां थे? अमित शाह ने कल सभी दलों की बैठक ली, जिसमें आप पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस के नेता भी उपस्थित थे।''

अजीत डोभाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, बोले- इंशाअल्लह अमन होगा

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में भड़की हिंसा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की तंग गलियों तक का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों

से बातचीत की। अजीत डोभाल ने कहा कि मैं पूरे इलाके में घूमा। लोग एकता चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। कुछ 10-20 अपराधी हिंसा फैला रहे हैं। इस बीच बुर्का पहनी हुई एक लड़की अजीत डोभाल से बातचीत करने आई और अपनी आपबीती सुनाई। बता दें कि स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए डोभाल ने कहा कि इंशाअल्लाह यहां पर अमन होगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पर यहां आया हूं। अब इस इलाके में पूरी शांति है।

आरक्षण नीति खत्म नहीं की जायेगी-अमरिन्दर सिंह

■ चंडीगढ़/विजय कुमार

छठा वेतन आयोग मौजूदा वर्ष में लागू होगा

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा आज ऐलान किया गया कि आरक्षण नीति, जिसमें तरक्कियों के लिए आरक्षण भी शामिल है, रा%य के अंदर जारी रहेगा औरि इसको ख़त्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कुछ विधायकों द्वारा प्रकट किए गए संदेहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा यह पहले ही मुकम्मल रूप में स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण नीति जारी रहेगी, उनको यह समझ नहीं आ रही कि विरोधी पक्ष द्वारा इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा वादा किये गए 9 नुक्तों में से एक के अनुसार आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्गों के लिए न केवल शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण में वृद्धि करके 15 फीसदी किया गया है बल्कि उनकी योग्यता में वृद्धि करके इसको 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया है।

विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि 6वें वेतन आयोग की सिफारशों को अमल में लाने का काम प्रगति अधीन है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू की जायेगी और उम्मीद है कि यह मौजूदा वर्ष में ही लागू हो जाये। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार पूरी वचनबद्धता से विभिन्न नीतियों और प्रोग्रामों को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहना रहे मुलाज़िमों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

17 एवं 18 मार्च को एल.पी.यू में रखा जायेगा राज्य स्तरीय पंजाब प्लेसमैंट मेला

अलग-अलग शैक्षणिक संस्थाओं के साथ की मीटिंग

■ जालंधर/न्यूज नेटवर्क

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) श्री विशेष सारंगल द्वारा आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ 17 एवं 18 मार्च को लवली प्रोफैसनल युनिवर्सिटी में करवाये जा रहे पंजाब प्लेसमैंट मेले से संबंधित बैठक की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) श्री विशेष सारंगल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लवली प्रोफैशनल युनिवर्सिटी में 17 एवं 18 मार्च को राज्य स्तरीय पंजाब प्लेसमैंट मेला करवाया जा रहा है उन्होने शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या 60 प्रतिशत अंको के साथ डिप्लोमा किया है का अधिक से अधिक इस मेले में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि इस मेले मे सिर्फ वही कंपनिया पहुँच कर रही है जो 3 लाख रुपये प्रति वर्ष पैकेज दे रही है। उन्होने शैक्षणिक संस्थाओं से कहा कि जिला प्रशासन से तालमेल करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले से संबंधित अधिक से अधिक विज्ञापनों को विश्वसनीय बनाया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा मेले में पहुँच किया जा सके। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कहा कि राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा ये प्लेसमैंट मेला नौजवानों के लिए रोजगार के नये रास्ते खोलेगा।

मुख्यमंत्री पंजाब के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा घर-घर रोजगार योजना के तहत यह एक विशेष प्रयास है। उन्होने कहा कि यह मेला नौजवानों को रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगी ताकि वे सम्मान और गौरव के साथ आपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेला एक तरफ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्राप्त करवायेगा तो दूसरी ओर स्थानीय उद्योगपतियों को कुशल श्रमीकों की प्राप्ती के उदेश्य को पूरा करेगी । इस अवसर पर डिप्टी डायरैक्टर रोजगार सजृन श्रीमती सुनीता कल्याण, डिप्टी डीबीईई सीईओ श्री दीपक भल्ला, रोजगार अधिकारी श्रीमती डिंपल थापर, कैरियर काउंसलर श्री जसबीर सिंह और श्री हरमनप्रीत सिंह एवं अन्य उपस्थित थे।

सेवा केन्द्रों की कार्याप्राणली पर सख्त नजर रखने के आदेश-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर

■ जालंधर/न्यूज नेटवर्क

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्री जसबीर सिंह ने समूह उप मंडल मैस्ट्रेटों को निर्देश दिये कि लोगो को समय अनुसार सुचारू ढंग से सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सेवा केन्द्रों के कार्याप्राणली पर कडी नजर रखी जाये। जिला प्रशासकी कंपलैक्स में बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी श्री जसबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आम लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उदेश्य के अंतर्गत सेवा केंद्र खोले गये हैं, इसलिए इस काम में किसी प्रकार की अनदेखी को सहन नही किया जायेगा उन्होने कहा कि सेवा केन्द्रों में कर्मचारियों के काम काज का निरीक्षण और प्राप्त प्रर्थानापत्रों को समय पर निपटाने को विश्वसनीय बनाया जाये जिससे लोगों की किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाने में सेवा केन्द्रों द्वारा दिखाई गई लापरवारी के प्रति जीरों टोलरैंस नीति को अपनाया गया है और सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यावाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों को कहा कि सभी सेवा केन्द्रों के बाहर फिस केबैनर लगाए जाये। उन्होंने यह भी बताया कि सेवा केन्द्रों की मुरम्मत का काम चल रहा है। इस मौके उप मंडल मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल, राहुल सिंधु, डा.संजीव कुमार शर्मा, विनीत कुमार और डा.जय इन्द्र सिंह के अतिरिक्त अन्य भी उपस्थित थे।

सालगिरह की शुभकामनाएं

स. बलविन्द्र सिंह व उनकी पत्नी बलविन्द्र कौर की जालंधर ब्रीज की तरफ से सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL

SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR

WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin